पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्रवाद संख्या- 8207/2022

==========

पप्पु कुमार पांडे, पुत्र, केदार नाथ पांडे, निवासी गाँव- जगदीशपुर, थाना- पीरपैंती, जिला- भागलपुर

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग (पुलिस), बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना द्वारा अपने सचिव
4. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।
5. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।
6. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

==========

A. **भारत का संविधान-असाधारण क्षेत्राधिकार- न्यायसंगत क्षेत्राधिकार-अनुच्छेद 226-प्राथमिक सिद्धांत-पीड़ित व्यक्ति-पर्याप्त कारण के बिना-अदालत का दरवाजा खटखटाता है-अपनी मर्जी से किसी रियायत की आवश्यकता नहीं-विलंब और शिथिलता के आधार पर-याचिका**

खारिज करने योग्य है - संदर्भित- (चेन्नई मेट्रोपौलिटन वाटर सप्लाई एंड चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी. टी. मुरली बाबू (2014) 4 एस. *सी. सी. 108; उत्तरांचल और अन्य राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी और अन्य 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6627; सी. जैकब बनाम भूविज्ञान और खनन निदेशक और अन्य ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 264; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आर. के. जलपुरी और अन्य ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3006; तमिलनाडु राज्य बनाम शेषाचलम (2007) 10 एस. सी. सी. 137; पी. एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 152; उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा (2010) 6 एस. सी. सी. 777) (कंडिका-10 -12).*

B. **नियुक्ति और चयन प्रक्रिया-समादेश-6 वर्षों की समाप्ति के बाद-कोई राहत नहीं दी जा सकती-अंतिम चयन सूची की समाप्ति-पक्षों का गैर-प्रत्युत्तर (प्रत्युत्तर न देना)-समादेश खारिज करने योग्य है। (कंडिका-13), (संदर्भितः- उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा (2010) 6 एस. सी. सी. 777, कंडिका-16**

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्रवाद संख्या- 8207/2022

==========

पप्पु कुमार पांडे, पुत्र, केदार नाथ पांडे, निवासी गाँव- जगदीशपुर, थाना- पीरपैंती, जिला- भागलपुर

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग (पुलिस), बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना द्वारा अपने सचिव
4. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।
5. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।
6. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:-

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री हर्ष अनुज, अधिवक्ता

: श्री अजीत कुमार सिंह,

राज्य के अधिवक्ता : श्री मनीष कुमार (जीपी-4)

प्रतिवादी बी. पी. एस. सी. के लिए : श्री कौशल के. झा, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्री अमृतेश कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः06-02-2024

1. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वे सहायक अभियोजन अधिकारियों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे बाद में "बी. पी. एस. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा ली गयी प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-42/2011 मे याचिकाकर्ता द्वारा हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून और सामान्य ज्ञान विषयों में प्राप्त अंकों को 90 अंकों के साथ जोड़ने के बाद याचिकाकर्ता की अंक- पत्रक को संशोधित करें और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दें।)

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण उसने 2011 के विज्ञापन संख्या 42 के अनुसरण में आवेदन पत्र भरा था और 23.03.2014 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुआ था, जिसमें उसने अर्हता प्राप्त की थी।याचिकाकर्ता तब वर्ष 2015 में मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुआ था, जिसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता का नाम योग्यता सूची में नहीं मिला, इसलिए वह

साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि उसने 524 अंक प्राप्त किए थे, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक 532 निर्धारित किए गए थे।यह याचिकाकर्ता का मामला है कि चूंकि उसे अधिक अंकों की उम्मीद थी, इसलिए उसने परीक्षा की प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक आर. टी. आई. आवेदन दायर किया था, जिसके बाद उसे मार्च 2021 के महीने में लिखित परीक्षा की प्रति प्रदान की गई थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उसने हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ के पेपर में 90 अंक प्राप्त किए थे, हालांकि, इसे 81 अंकों में संशोधित किया गया था, जो कि प्रश्न संख्या के खिलाफ उसके द्वारा प्राप्त 17 अंकों के बराबर था। 2, इसे घटाकर 14 अंक कर दिया गया, जबकि 19 अंक, प्रश्न संख्या के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्त किए गए, इसे घटाकर 13 अंक कर दिया गया।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न सं. 3 (बी) में याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के 10 में से '0' अंक दिए गए हैं और इसी तरह सामान्य ज्ञान परीक्षा में भी उसे प्रश्न संख्या 7(डी) और 2(जी) में '0' अंक दिए गए हैं। हालांकि, उन्होंने वहां भी सही उत्तर दिया था।

3. इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला है कि यदि याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका को चिह्नित करने में उपरोक्त विसंगति को ठीक किया जाता है, तो याचिकाकर्ता कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करेगा और परिणामस्वरूप साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पात्र हो जाएगा, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं को उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाता सं. 3 से 6 तक (बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा है कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित 2011 का विज्ञापन संख्या 2 बी. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो पुलिस (गृह विभाग), बिहार सरकार, पटना द्वारा भेजी गई दिनांक 27.12.2010 की

मांग के अनुसार था।याचिकाकर्ता ने जारी किये गए उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था, वह 30.03.2014 को पी. टी. परीक्षा में उपस्थित हुआ था। और उसी में उत्तीर्ण हुए, जिसके बाद वे मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए, हालाँकि, उन्हें असफल घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 532 (अनारक्षित श्रेणी) के कट-ऑफ अंकों के मुकाबले 524 अंक प्राप्त किया थे।अंतिम परिणाम 14.06.2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों की सिफारिशों को संबंधित विभागों को भेजा गया था, जिसके बाद नियुक्तियां भी की गई हैं और अब चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज करने योग्य है, विशेष रूप से याचिकाकर्ता की ओर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी और देरी के कारण क्योंकि वर्तमान रिट याचिका 14.06.2017 पर परिणाम के प्रकाशन के लगभग 5 साल बाद दायर की गई है, यानी केवल मई 2022 के महीने में।

5. प्रतिवादी-बी. पी. एस. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा है कि परीक्षा आयोजित होने और आयोग के कार्यालय में उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होने के बाद, परीक्षा के प्रभारी अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेख में प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को एक दोहरी कोडिंग प्रणाली सौंपी जाती है। उपरोक्त लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को पहले उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेज पर अनुक्रमांक और उम्मीदवारों के नाम वाले फ्लैप को यादृच्छिक रूप से उत्तर पुस्तिकाओं पर निर्दिष्ट स्थानो पर एक जोड़ी क्रमांकित स्टिकर चिपकाकर कूटबद्ध किया जाता है। रोल नंबर, उम्मीदवारों के नाम वाले फ्लैप को अलग किया जाता है और सीलबंद स्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम में अलग से रखा जाता है। पहले कोडिंग का पूरा काम आयोग के आदेश से गठित एक अलग दल द्वारा किया जाता है। इसके बाद, दूसरा कोडिंग कार्य इसी तरह किया जाता है और दूसरे कोड के साथ पहले कोड वाले फ्लैप को स्ट्रॉन्ग रूम में अलग से रखा जाता है। द्वितीय कोडिंग का पूरा काम आयोग की एक अन्य टीम द्वारा गोपनीय तरीके से किया जाता है। इस तरह उत्तर पुस्तिका में केवल दूसरा कोड बचा रहता

है। इस प्रकार, उम्मीदवार की पहचान (नाम, लिंग, धर्म, जाति, आदि) किसी को भी ज्ञात नहीं है। अंक कवर पेज के शेष भाग पर दिए जाते हैं जिसमें केवल दूसरा कोड होता है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग के कार्यालय में डिकोड किया जाता है और अब इस स्तर पर, उम्मीदवारों के रोल एन. ओ. एस. प्रतिबिंबित होते हैं और फिर एक योग्यता सूची तैयार की जाती है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि कोडिंग के चरण तक, उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को प्रकट करने का कोई मौका नहीं है।

6. प्रतिवादी-बी. पी. एस. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आयोग परीक्षकों के साथ प्रमुख परीक्षक की बैठकों की व्यवस्था करता है और पत्रों के मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए, एक या अधिक मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जो फिर प्रश्नों और उनके उचित उत्तरों पर अच्छी तरह से चर्चा करते हैं और मूल्यांकन कार्य शुरू करने से पहले मूल्यांकन का स्पष्ट मानक तय करते हैं। प्रमुख परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक परीक्षक द्वारा पालन किए जा रहे मूल्यांकन के निर्धारित मानक की बारीकी से निगरानी करता है और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय यदि उसे किसी परीक्षक की ओर से कोई विचलन दिखाई देता है तो उनका मार्गदर्शन करता है और फिर वह या तो परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की पुष्टि करता है या इसे ऊपर या नीचे की ओर संशोधित करता है और उत्तर पुस्तिका पर दिए गए आवश्यक अंकों को इंगित करता है।

7. इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन योग्य और अनुभवी परीक्षकों द्वारा उचित सावधानी के साथ किया गया है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं की ठीक से जांच की गई है और अंकों का सारणीकरण बहुत सावधानी से किया गया है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के अनुसार परीक्षक/प्रमुख परीक्षक द्वारा अंक दिए

गए हैं। याचिकाकर्ता से संबंधित विवरण बी. पी. एस. सी. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ नंबर 9 में उल्लिखित हैं, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

"(क) यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता को परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या 2 के लिए 17 अंक दिए गए जो उनकी हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ की उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 5 से स्पष्ट है। मुख्य परीक्षक ने प्रश्न संख्या 2 के अंकों को 17 से संशोधित कर 14 कर दिया है। प्रमुख परीक्षक ने पृष्ठ संख्या 5 और प्रथम पृष्ठ पर भी अपना प्रारंभिक लेख लिखा था। इस प्रकार, प्रमुख परीक्षक द्वारा बदले गए अंक याचिकाकर्ता के प्रदर्शन के अनुसार हैं।

(ख) यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता को प्रश्न संख्या 4 (ए) के लिए 14 अंक और प्रश्न संख्या 4 (बी) के लिए 5 अंक दिए गए हैं, परीक्षक द्वारा कुल 14+5 = 19 अंक जो पृष्ठ संख्या से स्पष्ट है। उनकी हिंदू कानून और मुस्लिम कानून की उत्तर पुस्तिका में से 15 से 17 प्रमुख परीक्षक ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 15 और 17 पर प्रश्न 4 (ए) के अंकों को 14 से संशोधित कर 10 और प्रश्न 4 (बी) के अंकों को 5 से संशोधित कर 3 कुल 10 +3 = 13 पेज, उत्तर पुस्तिका के पेज संख्या 15 और 17 पर कर दिया है।प्रमुख परीक्षक ने भी इन पृष्ठों पर अपना आद्यादार किया था।इस प्रकार, प्रमुख परीक्षक द्वारा अंकों में परिवर्तन उसके प्रदर्शन के अनुसार होता है।

(ग) यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता को प्रश्न संख्या के लिए 14 अंक दिए गए हैं। 3 (ए) पृष्ठ संख्या पर। प्रश्न संख्या के लिए 10 और 0 (शून्य) अंक। 3 (बी) पृष्ठ संख्या में परीक्षक द्वारा। उनके प्रदर्शन के अनुसार हिंदू कानून और मुस्लिम कानून की उनकी उत्तर पुस्तिका में से 33(घ) यहां यह उल्लेख करना

उचित है कि याचिकाकर्ता को सामान्य ज्ञान की उत्तर पुस्तिका में परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या 7 (घ) और 7 (छ) के लिए 0 (शून्य) पृष्ठ 7 पर दिए गए हैं।"

8. प्रतिवादी बी.पी.एस.सी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं में अंक दिए जाते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 की सिविल अपील संख्या 5046 में इस मुद्दे का फैसला किया है और (2004) 6 एस. सी. सी. 714 (प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम। अध्यक्ष, बी. पी. एस. सी.), अनुच्छेद सं. 7 से 9 जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः-

"7. हमने अपीलार्थी (रिट याचिकाकर्ता) को व्यक्तिगत रूप से और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है। विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश को सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने में उचित ठहराया गया था। आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए पूछने का हकदार हो। जांच के लिए केवल एक प्रावधान है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को यह जांचने के उद्देश्य से देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के अंकों के योग में कोई गलती हुई है और उन्हें उत्तर पुस्तिका के पहले कवर पेज पर सही ढंग से नोट किया गया है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई। संबंधित नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रश्न की महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ [(1984) 4 एस सी सी: ए. आई. आर 1984 एस. सी 1543 के मामले में काफी विस्तार से जांच की गई थी। इस मामले में, एक उम्मीदवार द्वारा उस प्रभाव के लिए किए गए आवेदन पर सत्यापन (अंकों की जांच) के लिए प्रासंगिक नियम प्रदान किए गए हैं। कुछ छात्रों ने रिट याचिकाएं दायर कर प्रार्थना की कि उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए और बोर्ड को ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाए जो याचिकाकर्ता निरीक्षण के बाद मांग कर सकते हैं।उच्च न्यायालय ने कहा कि अंकों के सत्यापन के लिए प्रावधान करने वाले नियम ने परीक्षार्थियों को प्रकटीकरण और निरीक्षण की मांग करने और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के लिए एक निहित शक्ति दी है। उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में जो एक परीक्षक को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार प्रदान करता है, ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आयोग के प्रासंगिक नियम के तहत किसी उम्मीदवार को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का कोई प्रावधान नहीं है।ऐसी स्थिति में, रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पूरी तरह से असमर्थनीय थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए सुझाव को अपनाने से व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी। कई उम्मीदवार मौका लेना पसंद कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, अदालत अलग-अलग तारीखों पर आदेश पारित करेगी जब रिट याचिकाएं दायर की

जाएंगी। आयोग को फिर से मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को अलग-अलग उम्मीदवारों की प्रतियां भेजनी होंगी, जिसमें समय लगना तय है।आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण, अंतिम परिणाम की घोषणा में अनावश्यक रूप से देरी होगी और रिक्तियां लंबे समय तक नहीं भरी जाएंगी। यदि कोई उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन में कम अंक प्राप्त करता है तो क्या होगा? वह एक याचिका के साथ आगे आ सकता है कि मूल रूप से उसे दिए गए अंकों को ध्यान में रखा जाए। विषय पर स्पष्ट नियमों का अभाव कई समस्याओं को जन्म दे सकता है और व्यापक हित में, उनसे बचा जाना चाहिए।

9. अन्यथा भी, जिस तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश ने सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया था, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उत्तर पुस्तिका न्यायालय द्वारा सीधे पटना विश्वविद्यालय के कुलसचिव या विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को नहीं भेजी गई थी। उत्तर पुस्तिका की एक फोटोकॉपी पटना विश्वविद्यालय के स्थायी वकील को सौंपी गई, जिन्होंने कुछ समय बाद उसे अदालत को वापस कर दिया और इस आशय का एक बयान दिया गया कि पटना विज्ञान महाविद्यालय के दो शिक्षकों द्वारा इसकी जांच की गई थी। अदालत में शिक्षकों के नामों का खुलासा भी नहीं किया गया था। विचाराधीन परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें उम्मीदवार की तुलनात्मक योग्यता का आकलन किया जाता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में एक समान मानक लागू किया जाए।यह आयोग का विशिष्ट मामला है कि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की एक केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें विभिन्न परीक्षक अन्य परीक्षकों की सहायता से प्रमुख परीक्षक द्वारा तैयार किए गए मॉडल उत्तरों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत लेटर्स पेटेंट अपील में

यह अनुरोध किया गया था और इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि पटना विज्ञान महाविद्यालय के दो शिक्षकों को आदर्श उत्तर प्रदान नहीं किया गया था। विभिन्न परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने में मानकों में भिन्नता हो सकती है। जिस तरह से उत्तर-पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया था, उसमें दिए गए अंकों को पवित्र नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आयोग को सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी के अंकों को 63 मानने के लिए जारी किए गए निर्देश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

9. इस प्रकार बी. पी. एस. सी. के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि गुण-दोष के आधार पर भी, याचिकाकर्ता को कोई मामला नहीं मिला है और वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त है।

10. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 14.06.2017 पर परिणामों के प्रकाशन के लगभग 5 साल बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कानून अच्छी तरह से स्थापित है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, संवैधानिक न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, साथ ही साथ खुद को प्राथमिक सिद्धांत पर जीवित रखना चाहिए कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति, पर्याप्त कारण के बिना, अपने अवकाश या खुशी से अदालत का देर से संपर्क करता है, तो रिट कोर्ट को ऐसे आलसी व्यक्ति को कोई अनुग्रह प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है और केवल देरी और विलंब के आधार पर, रिट कोर्ट को याचिका को प्रारम्भ में ही खारिज कर देना चाहिए। इस संबंध में, निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जाना चाहिएः-

"(i) **चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी. टी. मुरली बाबू, (2014) 4 एस. सी. सी. 108** में प्रतिवेदित किया गया।

(ii) **उत्तरांचल राज्य बनाम उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी एंड ओ. आर. एस. ने 2013 में ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6627** में प्रतिवेदित किया गया।

(iii) **सी. जैकब बनाम निदेशक भूविज्ञान और खनन और ए. एन. आर. ने ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 264** में प्रतिवेदित किया गया।

(iv) **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम आर. के. ज़लपुरी और अन्य, ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3006** में प्रतिवेदित किया गया।

(v) **तमिलनाडु राज्य बनाम शेषाचलम, (2007) 10 एस. सी. सी. 137** में प्रतिवेदित किया गया।"

11. वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी. एस. सदाशिवस्वामी बनाम, तमिलनाडु राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 152** में प्रतिवेदित, मामले में दिए एक निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी सेवा मामले/पदोन्नति मामले में, एक व्यथित व्यक्ति को कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के कम से कम छह महीने के भीतर या अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और यह न्यायालयों के लिए विवेकाधिकार का एक सही और बुद्धिमान अभ्यास होगा कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करें, उन व्यक्तियों के मामले में जो राहत के लिए तेजी से संपर्क नहीं करते हैं और ऐसी याचिकाओं को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी याचिकाओं

पर विचार करना न्यायालय के समय की बर्बादी है। यही न्यायालय के कार्य को बाधित करता है और वैध शिकायतों पर विचार करने में न्यायालय के कार्य को बाधित करता है।

12. **चेन्नई महानगर में जल आपूर्ति और मलजल निकासी बोर्ड एंड अन्य** (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि चार साल की देरी के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाकर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को देर से चुनौती देना किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं है और केवल देरी के आधार पर, रिट अदालत को याचिका को प्रारम्भ में ही खारिज कर देना चाहिए था।

13. फिर भी मामले का एक अन्य पहलू यह है कि प्रत्यर्थी-बी. पी. एस. सी. ने संबंधित विभागों को सफल उम्मीदवारों की सिफारिशें की हैं, जिसके बाद नियुक्तियां भी की गई हैं और चयन प्रक्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई है, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि इस मोड़ पर, लगभग छह साल से अधिक की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, जिसने अन्यथा इस न्यायालय से देर से संपर्क किया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने न तो अंतिम चयन सूची पर हमला किया है और न ही सफल उम्मीदवारों को वर्तमान रिट याचिका के पक्षकार के रूप में बनाया है, जिससे वर्तमान रिट याचिका उत्तरदायी है। याचिका में आवश्यक पक्षों के गैर-उत्तरदायी होने के लिए खारिज किया जाना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना लाभदायक होगा। **उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा (2010) 6 एस. सी. सी. 777** के मामले में दिए निर्णय का उल्लेख करना लाभदायक होगा, पैराग्राफ नं.16, जिसका पुनरुत्पादन नीचे किया जा रहा हैः-

> *"16. एक चयन सूची को नियुक्तियों के उद्देश्य के लिए एक भंडार के रूप में नहीं माना जा सकता है, उस रिक्ति को उस सूची से नाम लेते हुए भरा जा सकता है जब भी इसकी आवश्यकता हो। यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि यदि उम्मीदवार चयन सूची*

की समाप्ति के बाद अदालत का दरवाजा खटता है तो उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है। यदि चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, चयन सूची समाप्त हो गई है और नियुक्तियां की गई हैं, तो अदालत द्वारा विलंबित चरण में कोई राहत नहीं दी जा सकती है। (जे. अशोक कुमार बनाम ए. पी. राज्य [(1996) 3 एस. सी. सी. 320:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 707], बिहार राज्य बनाम मोहम्मद कलीमुद्दीन [(1996) 2 एस. सी. सी 7:1996 एससीसी (एल एंड एस) 389:(1996) 32 एटीसी 821:ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1145], यू. पी. राज्य बनामहरीश चंद्र [(1996) 9 एससीसी 309:1996 एससीसी (एल एंड एस) 1240:ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2173], सुषमा सूरी बनाम एन. सी. टी. दिल्ली की सरकार [(1999) 1 एस. सी. सी. 330:1999 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 208], यू. पी. राज्य बनामराम स्वरूप सरोज [(2000) 3 एस. सी. सी. 699], के. तुलसीधरन बनाम केरल राज्य लोक सेवा आयोग [(2007) 6 एस. सी. सी. 190:(2007) 2 एससीसी (एल एंड एस) 427], दीपा कीज़ बनाम केरल एसईबी [(2007) 6 एससीसी 194:(2007) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 430] और सुभा बी. नायर [(2008) 7 एस. सी. सी. 210:(2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 409]।)"

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए यह खारिज किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सौरभ/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।